



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 382]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 1979/अग्राहायण 14, 1901

No. 382]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 1979/AGRAHAYANA 14, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation.

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1979

सं० 672 (अ):—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित
उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनाधर्म प्रकाशित की जा रही है:—

यतः मुझे, भारत के राष्ट्रपति, नीचम संजीव रेड्डी को केरल राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और मुझे प्राप्त इस रिपोर्ट और अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान जिसे हमें इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं:—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या एतद्वारा प्रयोज्य सभी शक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूँ;

(ख) घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियाँ संसद के प्राधिकार द्वारा या अर्थात् प्रयोज्य होंगी; और

(ग) निम्नलिखित प्रावृत्तिक और परिणामिक उपबन्ध करता हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिये मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात्:—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के आधार पर अपने हाथ में लिये गये कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग

करने में, मेरे लिये भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिन तक मैं ठीक समझूँ उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा;

(ii) उस राज्य के सम्बन्ध में संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रवर्तन का एतद्वारा निश्चित किया जाता है, अर्थात्:—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल का निर्देश करने से है;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है;

अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्यों का मंत्रियों के बीच आवंटन से है; अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प के पारित किये जाने से है;

अनुच्छेद 174 का खंड (1) और खंड (2) का उप-खंड (क); अनुच्छेद 175 से 178 तक जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं; अनुच्छेद 179 का खंड (ख) और (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक और अनुच्छेद 180 और 181;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सम्बलनों और भत्तों से है; अनुच्छेद 188, 189, 193, 194, 195 तथा 196; अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4);

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सम्बलनों और भत्तों से है; अनुच्छेद 208

से 211 तक जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं; अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक; और अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध आपन सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है;

(iii) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जायेगा और उसमें राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहाँ तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ जब तक कि संघर्ष में अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद् के प्रति निदेश लगाया जायेगा, और विधिस्तथा अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद् या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जायेगा;

परन्तु इसमें कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं, अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से 4 तक जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को इस खंड के उपखंड (1) के अधीन उस सीमा तक जहाँ तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

(iv) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या एतद्द्वारा बनाये गये अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जायेगा मानों उसके अन्तर्गत इस उपबोधना के आश्रय पर संसद् द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) और केवल राज्य में व्याप्त केंद्र नियंत्रण तथा साधारण खंड अधिनियम 1125 (1125 का अधिनियम 7) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है, और साधारण खंड अधिनियम 1897 (1897 के खंड) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावों होगा मानों यह उक्त राज्य विधान मंडल का अधिनियम हो।

कैम्प बाबाई :

5 दिसम्बर, 1979.

नेलम संजीव रेड्डी,

राष्ट्रपति

[पं. 5/11013/4/79-सी०एच०आर०]

नई दिल्ली 5 दिसम्बर 1979.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1979

G.S.R. 672(E).—The following Proclamation by the President is published for general information :

Whereas, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, have received a report from the Governor of the State of Kerala and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution") ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State ;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament ; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely :—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State ;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely :—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislative of the State ;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India ;

articles 163 and 164 ;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State ;

article 167 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State ;

clause (1), and sub-clause (a) of clause (2), of article 174 ;

articles 175 to 178 (both inclusive) ;

clause (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181 ;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly ;

articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196, article 198; clause (3) and (4) of article 199

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; article 208 to 211 (both inclusive); the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213 ; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State ;

(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the House thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively.

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State ;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other autho-

rity referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Interpretation and General Clauses Act, 1125 (Act VII of 1125) as in force in the State of Kerala, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

Camp Bombay :

The 5th December, 1979

NEELAM SANJIVA REDDY,

President

[No. V/11013/4/79-CSR]

New Delhi :

The 5th December, 1979.

आदेश

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1979

सं०का०नि० 673(प्र):—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनाय प्रकाशित किया जा रहा है:—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज दिसम्बर, 1979 के पांचवें दिन आगे की गई उच्चापना के खंड (ग) के उपखंड (1) का अनुगुण करते हुए मैं एतद्वारा निदेश देता हूँ कि केवल राज्य सरकार के सभी कृत्य और गतिविधियों के अधीन या उस राज्य में प्रकृत किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या प्रयोज्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उच्चापना के खंड (क) के प्राचार पर अपने हाथ में ले लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण,

निदेशन और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोज्य होंगी।

कैम्प बम्बई :

5 दिसम्बर, 1979

नई दिल्ली :

5 दिसम्बर, 1979

नीलम संजीव रेड्डी,

राष्ट्रपति

[न० 5/11013/4/79-सी०एम०धारा०]

बी०जी० देशमुख, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th December, 1979

G.S.R. 673(E).—The following Order by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 5th day of December, 1979 by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Kerala and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

Camp Bombay :

The 5th December, 1979.

NEELAM SANJIVA REDDY,

[No. 5/11013/4/79-CSR]

New Delhi :

The 5th December, 1979.

President

B. G. DESHMUKH, Additional Secy.

